



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 23 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 12 फरवरी, 2014)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी “क”)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी “ख” तथा “ग”)
3. निधन के निदेश।
4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
5. श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद पौड़ी गढ़वाल के न्यायपंचायत कांडाखाल विकास खण्ड द्वाराखाल में पेयजल संकट के समाधान के सम्बन्ध में” श्री हर्षपति नैथानी, निवासी ग्राम महरगांव, पो0 कांडाखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
6. श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला कांडी, दुगड्डा मोटर मार्ग को हाट मिक्स कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री कपिल रतूड़ी, निवासी ग्राम सीला, पो0 भृगूखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्रीमती विजय बड़थवाल, सदस्य, विधान सभा, “जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवीखेत, स्यालना, चमस्यूल गहली मोटर मार्ग के अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री भाष्कर डबराल, निवासी ग्राम कूंतणी, पो0 डबोलीखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, “जनपद बागेश्वर के इण्टर कालेज सिरकोट के प्रांतीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में” श्री इन्द्र सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम हवीलकुलबान, पो0 सिरकोट, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा "जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा जखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल जखेड़ा का उच्चीकरण एवं प्रांतीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री ईश्वर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम जखेड़ा, पो0 जखेड़ा, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा, "जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्त क्वैराली का इण्टर में उच्चीकरण एवं प्रांतीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री ईश्वरी दत्त चौबे, निवासी ग्राम छती, पो0 मनकोट, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
11. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
12. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
13. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
14. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"घ")

15. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
16. वित्तमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। (15 मिनट)
17. वित्तमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, पारित किया जाय।
18. वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
19. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
20. विधान सभा क्षेत्र तल्ला सल्ट में कोई महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
21. विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की गरुड़ वृहद पेयजल के लम्बित प्रस्ताव की जांच के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

देहरादून :

दिनांक : 11 फरवरी, 2014

आज्ञा से,



(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



प्रथम सत्र, 2014
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 23 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 12 फरवरी, 2014)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

कुंवर प्रणव सिंह
'चैम्पियन'
03.02.2014

**क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों को शस्त्र लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व एक "प्रशिक्षण प्रमाण पत्र" की बाध्यता को अनिवार्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस बाध्यता से जन सामान्य को पहुंच रही कठिनाई से सरकार अवगत है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवासरत नागरिकों, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, को कितनी मुसीबत के साथ शूटिंग एकेडमी पहुंच कर उक्त प्रमाण पत्र हासिल करने होंगे जिसमें अकारण ही अपव्यय होगा ? क्या जनहित में सरकार उक्त सुविधा को प्रत्येक पुलिस थाने पर एक पृथक प्रशिक्षण खण्ड गठित कर नागरिकों को अल्प प्रशिक्षण प्रदान कर, उक्त "प्रशिक्षण प्रमाण पत्र" उपलब्ध करायेगी, जिससे कि नागरिक इस अत्यन्त असुविधा से बच सकेंगे, और अपनी निजी सुरक्षा को करने में सक्षम हो जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह

श्री चन्द्रशेखर
03.02.2014

**क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक भगवानपुर के अधिकतर गावों में पेयजल की गम्भीर समस्या है तथा इन गावों में नये हैण्ड पम्पों का लगना बहुत आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ब्लाकों में हैण्ड पम्प लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल

नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत
प्रथम सत्र 2014 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री भीमलाल आर्य
17.06.2013

*01. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के सीमान्त जनसंख्या एवं क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़े विकास खण्ड- भिलंगना का पुनर्गठन कर जनहित तथा विकास हित में नवीन बाल गंगा विकास खण्ड का सृजन किये जाने पर सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज

नत्थी "ग"

तारांकित प्रश्न

- श्री बंशीधर भगत
18.12.2013
- *01. **अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।**
क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के तराई भावर क्षेत्र रामनगर, हल्द्वानी और कालाढूंगी में विगत 40-50 सालों से काबिज किसानों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों?
- राजस्व
- श्री मयूख महर
20.12.2013
- *02. **आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।**
क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मिशन चण्डाक की सरकारी वन भूमि को भू माफियाओं से छुड़ाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कार्य की जांच हेतु नियुक्त कुमायूं कमिश्नर की जांच रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर उक्त सरकारी भूमि को अवमुक्त करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों?
- राजस्व
- श्री महावीर सिंह
रांगड़
24.12.2013
- *03. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र के चम्बा-मसूरी फल पट्टी को भी सितारगंज की भांति भूमिधर अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- राजस्व
- डा0 जीतराम
26.12.2013
- *04. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में खण्ड विकास अधिकारियों तथा ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है और ये पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी ?
- ग्राम्य विकास
- श्री ललित फर्स्वाण
27.12.2013
श्री प्रेम चंद
अग्रवाल
31.12.2013
- *05. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय जनपदों के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उठाने से पूर्व इस बात की पुष्टि की जाती है कि अनाज खाने लायक है ? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आये दिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सड़ा खाद्यान्न वितरण की शिकायतों के क्या कारण हैं ?
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
- श्री ललित फर्स्वाण
27.12.2013
- *06. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं है में कैरोसिन की काफी कमी हो रही है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र मल्ला दानपुर व कमस्यार क्षेत्र में कैरोसिन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कैरोसिन की आपूर्ति सुचारु करने हेतु क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

श्री भीमलाल आर्य
31.12.2013

*7. **अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**

नियोजन

क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपदवार राज्य सरकार ने राज्य स्थापना के पश्चात् प्रतिवर्ष अब तक राज्य सरकार द्वारा कितना परिव्यय निर्धारित किया गया एवं इस परिव्यय के सापेक्ष आय-व्यय एवं व्यय की प्रत्येक जनपदवार जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजना के अधीन अयोजनागत व आयोगोत्तर पक्षों में प्राविधान एवं व्यय का प्रतिशत जनपदवार कितना है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राज्य सरकार प्रत्येक जनपद को विगत वर्षों से कम किये गये आवंटन के सापेक्ष आनुपातिक रूप से आय-व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री नवप्रभात
17.05.2013

1. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये विकास खण्ड सृजित करने के क्या मानक हैं ? नये विकास खण्ड के सृजन के लिये योजना आयोग भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है ? यदि हां, तो योजना आयोग के दिशा निर्देश क्या हैं तथा विकास खण्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं कार्यालय संचालन का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता है ? क्या योजना आयोग भारत सरकार विकास खण्ड को कोई सीधी सहायता देता है ?

पंचायती
राज

श्री सुरेन्द्र सिंह
जीना
21.05.2013

2. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग में ठेकेदारी के आधार पर श्रमिकों व कर्मचारियों को रखा जाता है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2007 के बाद से अब तक कितने श्रमिकों कर्मचारियों को किन-किन स्थानों पर किस कम्पनी या ठेकेदार के द्वारा लगाया गया ? क्या सरकार उक्त का जिलेवार पूर्ण विवरण देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई

श्री गणेश जोशी
14.06.2013

3. **विभिन्न विभागों से संबंधित एवं अस्पष्टता के आधार पर।**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत कैंट क्षेत्र वासियों को राज्य सरकार की जेएनयूआरएम, बीपीएल कार्ड आदि योजनओं का लाभ नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कैंटवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनओं का लाभ दिलाने के लिए विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य
विकास

श्री चन्दन राम
दास
27.06.2013

4. क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2012-13 व 2013-14 की जिला योजना में बागेश्वर जनपद का परिव्यय कितना था तथा स्वीकृत परिव्यय के अनुपात में अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त हुई है तथा अवमुक्त धनराशि में से विकास खण्डवार अवमुक्त धनराशि का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड गरूड़ में धनराशि आवंटन न करने का क्या कारण है ?

पंचायती
राज

श्री ललित फर्स्वार्ण 08.08.2013 5. क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा सं० 615/2012 द्वारा जनपद बागेश्वर के चौड़ास्थल एवं कांडा में ब्लॉकों के सृजन हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों में प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? **पंचायती राज**

अतारांकित प्रश्न

श्री विशन सिंह चुफाल 17.12.2013 01. क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करें कि प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कुल कितने प्रखण्ड कार्यालय हैं तथा अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या कितनी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के पद पर कोई नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो क्या वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **ग्रामीण अभियंत्रण**

श्री नवप्रभात 18.12.2013 02. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर विकास खण्ड में उदियाबाग नाले पर बनी बेलावाला की नहर तथा पैदल मार्ग दैविक आपदा से क्षतिग्रस्त हुआ है ? यदि हां, तो इस नहर तथा मार्ग को पुनः बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? **आपदा प्रबन्धन**

श्री ललित फर्स्वार्ण 23.12.2013 03. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर में कुल 20 सहायक खाद्य निरीक्षकों में से वर्तमान में 4 ही सहायक खाद्य निरीक्षक ही कार्यरत हैं जबकि 1 सहायक खाद्य निरीक्षक 6 माह से मेडिकल पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायक खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**

श्री मयूख महर 24.12.2013 04. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के जाजर देवल (उर्ग) नामक स्थान पर ट्यूब वेल लगाने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस योजना का सिंचाई के अतिरिक्त क्षेत्र वासियों को पेयजल का भी लाभ मिल जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पिथौरागढ़ में इसके अतिरिक्त भी ट्यूब वेल लगाने की योजना विभाग के पास है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ? **सिंचाई**

डा० जीतराम 26.12.2013 05. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के थराली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 16-17 जून 2013 को आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त गावों उनीकाड, थराली, नारायणबगड़, नन्दप्रयाग, घाट एवं घिघराणा आदि ग्रामों की सरकार द्वारा सुरक्षा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **सिंचाई**

डा० जीतराम 26.12.2013 06. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में 59 ऐसी बस्तियां हैं जो कोर नेटवर्क में त्रुटिवश संयोजित दर्शायी गई हैं जबकि वास्तविक रूप में ये बस्तियां असंयोजित हैं ? यदि हां, तो ऐसी बस्तियों को संयोजित किये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक इन 59 बस्तियों को मोटर मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? **ग्राम्य विकास**

डा0 जीतराम 26.12.2013	07. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत माह जून, 2013 में आयी आपदा से ग्राम रतगांव के वंघाण गाड़ गदरे, पैर गदरे व गुया गदरे से हुए भूमि कटान को रोकने हेतु सरकार चैक डैम का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	8. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद के दुग को तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो दुग तहसील का शासनादेश कब तक जारी हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	राजस्व
श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	9. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में दैवीय आपदा से प्रभावित 42 गावों के पुनर्वास हेतु सर्वे किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	आपदा प्रबन्धन
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 30.12.2013	10. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के ग्राम प्रतीतनगर में सन् 2003 में मिनी खेल स्टेडियम की घोषणा हुई थी ? यदि हां, तो स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया और भविष्य में कब तक निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ताकि क्षेत्र के खिलाड़ियों को इसका समुचित लाभ मिल सके ?	खेल
श्री भीमलाल आर्य 30.12.2013	11. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी बांध के उपर सरकार आम जनता को यातायात की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	12. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के सीमान्त पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर विद्युत आपूर्ति सुचारु नहीं है कैरोसिन की काफी कमी हो रही है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र मल्ला दानपुर व कम्सयार क्षेत्र में कैरोसिन की आपूर्ति बराबर नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
श्री भीमलाल आर्य 30.12.2013	13. अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त। क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में कुल कितनी सिंचाई नहरें निर्मित हैं तथा कितनी सिंचाई नहरें निर्माणाधीन/प्रस्तावित हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि समस्त नहरों पर समय समय पर कितनी धनराशि खर्च हुई तथा उसका निविदा सहित ब्योरा उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	सिंचाई
श्री भीमलाल आर्य 30.12.2013	14. द्वितीय बुधवार के अता0 18 में स्थाना0 क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम प्रहरियों को वेतन प्रदान करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज

श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	15. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में संयुक्त परिवारों से अलग हो रहे परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	16. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर्वतीय जनपदों में भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर सरकारी सस्ते गल्ले के लाइसेंस के मानकों में शिथिलता प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इस संबंध में शासनादेश जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
श्री महावीर सिंह रांगड 30.12.2013	17. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कैरोसीन तेल की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कैरोसीन तेल की निर्धारित मात्रा में निश्चित समय पर आपूर्ति कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

नत्थी “घ”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 12 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

फरवरी, 2014

12 बुधवार

- 1— बजट पर सामान्य चर्चा।
- 2— विधायी कार्य
1—भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण
(15 मिनट)

13 गुरुवार

- | | | |
|---------------|----|--|
| अनुदान संख्या | 05 | निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| | 07 | वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| अनुदान संख्या | 06 | राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| | 18 | सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| | 20 | सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |

14 शुक्रवार

अवकाश (रविदास जयंती)

15 शनिवार

अवकाश

16 रविवार

अवकाश

17 सोमवार

- | | | |
|---------------|----|--|
| अनुदान संख्या | 12 | चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| अनुदान संख्या | 19 | ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| | 25 | खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| अनुदान संख्या | 26 | पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |
| | 29 | औद्योगिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
(15 मिनट) |

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

18 मंगलवार

अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान (15 मिनट)

अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान (15 मिनट)

अनुदान संख्या 15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

24 परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (30 मिनट)

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (30 मिनट)

19 बुधवार

अनुदान सं० 01 विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।

02 राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

03 मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

04 न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

08 आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट) —

09 लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।

10 पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट) —

14 सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट) —

21	उर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	(15 मिनट)	---
22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	(15 मिनट)	---
23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	(15 मिनट)	---
27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	(15 मिनट)	---

20 गुरुवार

1-विधायी कार्य।

1- उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

2-असरकारी कार्य (आधा दिन)